SBBL Gun	1
DBBL Gun	21
Other Guns	69
Mousers	44
Stickbombs	17
Other bombs	28
Rockets	1
Rocket Launchers	5
Rocket Detonators	166
Magazines	69
Rifles 3x3	41
Rifles 7·62	2
Rifles 315 bore	6
Automatic Rifles	1
Other rifles	36
Hand Grenades HE-36	14
Other Hand Grenades	30
Land Mines	6
Grenade Launcher	1
Carbines	1
Explosive material	2770 Gms.
Explosive Packets	99
Cartridges	11152

महिलाओं पर अत्याचार

3127. **श्री राम नरेश यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से अब तक देश में महिलाओं पर किये गये अत्याचारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से दहेज के कारण हत्या, अपहरण या बलात्कार की शिकार महिलाओं की श्रेणीवार और राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारें इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रही हैं ; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एम.एम. जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के दौरान महिलाओं पर किए गए अपराधों (श्रेणीवार) के उपलब्ध आंकड़ों को राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार सूची, अनुपत्र में दी गई है, [देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 63] ।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" विषय राज्य की सूची में शामिल हैं । महिलाओं के खिलाफ, होने वाले अपराधों सहित, अपराधों को दर्ज करना, उनका पता लगाना, जांच करना तथा उसकी रोकथाम करना, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है । कानून को अधिक कड़ा बनाने तथा महिलाओं पर होने वाले अपराधों से संबंधित अनुदेशों को कारगर ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने समय-समय पर सभी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे महिलाओं पर होने वाले अपराधों के सभी मामलों पर गंभीरता से ध्यान दें । ऐसे सभी मामलों को तुरन्त दर्ज करने, उनकी उचित स्तर पर जांच करवाने तथा न्यायालयों में शीघ्रता से मामले फाईल करने तथा उन पर तेजी से अनुवर्ती कार्रवाई करने के बारे में उन्हें विशिष्ट रूप से सलाह दी गई है ।

Financial Assistance to U.P. for combating terrorism

3128. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are giving financial assistance to the States for combating terrorism;

(b) whether any financial assistance has been provided to the U. P. Government; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) 'Public Order' being State subject, it is for the State Governments concerned to devise various methods and take concrete steps to improve law and order situation. The Central Government is providing all possible assistance to State Governments in this regard including financial assistance.

(b) and (c) An amount of Rs. 10 crores has been sanctioned to the State Government of Uttar Pradesh as grants-in-aid for operations against militants in the Terai area of the State.

Attack on Journalists

3129. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the police killed Mr. Ghulam Rasool and Mr. Vijaya Prasad Rao, Journalists in cold blood and the story of an encounter was a fake one intended to cover it as has been reportedly confirmed by the Editors Guild of India;

(b) if so, what action Government are taking in the matter; and

(c) whether Government have alerted the State Government about the growing attacks on journalists in various part of the Country;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) As per report received from the State Government of Andhra Pradesh, one Ghulam Rasool @Jagan, reporter of Telugu Daily (Udayam) and another person, Vijaya Prasad Rao @Vijaya were killed in an exchange of fire with police at Masjeedgudem (Rangareddy District) on 28-12-91.

(b) A Commission of inquiry headed by Justice Shri T. L. N. Reddy was appointed by the State Government to enquire into the facts leading